[2016] 9 एस.सी.आर. 220

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, धनबाद

बनाम

केन्दुआडीह कोलियरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता, एम/एस बीसीसीएल एवं अन्य

(नागरिक अपील सं. 11003, 2016)

21 नवंबर, 2016

[टी. एस. ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड और एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति]

औद्योगिक विवाद, - अवशोषण या नियमितीकरण - अट्ठासी मजदूर कोलियरी में टिंडल के रूप में कार्यरत थे - रोजगार की मांग करते हुए औद्योगिक विवाद - औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित पुरस्कार जिसमें प्रबंधन को निर्देश देने का आदेश कि जब भी वे नियमित कामगारों को नियुक्त करने का इरादा करेंगे, तो इन कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी - उक्त आदेश अंतिम हो गया - इसके बाद, मजदूरों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन की मांग की - हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई - प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि भविष्य में रिक्ति उत्पन्न होती है और पद का विज्ञापन किया जाता है, जिसके लिए मजदूर आवेदन करते हैं, तो उन्हें विचार किया जाएगा - अपील पर, यह पाया गया: न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित उच्च न्यायालय के पुरस्कार का अंतिम रूप हो गया और मजदूरों ने इसे कार्यान्वित करने की मांग की - मजदूरों का दावा उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होना चाहिए, जिसके द्वारा मजदूरों को भविष्य में प्रबंधन द्वारा रोजगार में प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया था - अपीलकर्ता द्वारा पहले उत्तरदाता की एक कोलियरी के संघ की कुछ कार्यवाहियों पर भरोसा करना, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रभागीय पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और न्यायाधिकरण के पुरस्कार को बहाल किया जिसमें बिना पिछली मजदूरी के पुनर्स्थापन दिया गया, सही नहीं - आगे, एक समिति की रिपोर्ट कि टिंडल के पद में कोई रिक्ति नहीं थी, जिसमें अट्ठासी मजदूर कार्यरत थे - इस परिप्रेक्ष्य में, प्रथम उत्तरदाता को अट्ठासी मजदूरों को चार लाख रुपये प्रति व्यक्ति का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, टिंडल की कुशल श्रेणी के मजदूरों के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में।

अट्ठासी मजदूर प्रथम उत्तरदाता की कोलियरी में टिंडल के रूप में कार्यरत थे। कोलियरी मजदूर संघ ने अट्ठासी मजदूरों के रोजगार की मांग करते हुए औद्योगिक विवाद उठाया। न्यायाधिकरण ने एक पुरस्कार पारित किया।

प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि वह वरिष्ठता के अनुसार मजदूरों का एक पैनल बनाए और एक वर्ष के भीतर टिंडल/उपयुक्त श्रेणी के कार्य में उन्हें समाहित या नियमित करे। प्रथम उत्तरदाता ने एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को संशोधित करते हुए प्रबंधन को निर्देश दिया कि जब भी वे नियमित मजदूरों को नियुक्त करना चाहते हैं, तो इन मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त आदेश अंतिम हो गया। इसके बाद,

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, धनबाद बनाम नियोक्ता 221 एम/एस बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी

मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए निपटाया कि पिछले आदेश के बाद से कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में रिक्ति उत्पन्न होती है और पद का विज्ञापन किया जाता है, जिसके लिए मजदूर आवेदन करते हैं, तो उन्हें पद के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद, समीक्षा याचिका को भी इसी शर्तों पर निपटा दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 अपीलकर्ता ने कुछ कार्यवाहियों पर भरोसा किया है जो प्रथम उत्तरदाता की एक कोलियरी में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के अनुरोध पर औद्योगिक न्यायाधिकरण में एक अलग संदर्भ में हुई थी, जिसमें सामान्य मजदूर श्रेणी नंबर 1 में सत्तर मजदूरों के नियमितीकरण का निर्देश देने वाला एक पुरस्कार पारित किया गया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय को रद्द कर दिया और पिछली मजदूरी के बिना पुनःस्थापन देने वाले न्यायाधिकरण के पुरस्कार को बहाल कर दिया। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिल सकती क्योंकि उस मामले में, संघ ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दी थी। वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संशोधित करते हुए उच्च न्यायालय का 18.05.2004 का निर्णय अंतिम हो गया। मजदूरों का दावा इसलिए उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न होना चाहिए जिसके द्वारा मजदूरों को भविष्य में प्रबंधन द्वारा रोजगार में प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया था। [पैरा 5, 6] [224-बी-सी, डी-जी]

1.2 प्रथम उत्तरदाता द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में देखा कि केन्दुआडीह कोलियरी या पूटकी बलिहारी क्षेत्र के संबंध में टिंडल, श्रेणी IV के पद में कोई रिक्ति नहीं है। केन्दुआडीह कोलियरी को बंद खदान बताया गया है। इस न्यायालय के *वर्कमेन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड* के निर्णय सीए 13953, 2015 दिनांक 3 अक्टूबर 2016 में, यह कारण बताए गए थे कि पुनःस्थापन देना व्यावहारिक क्यों नहीं होगा, विशेषकर जब से उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के निर्णय में इस तरह की राहत से इंकार किया गया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई। इस न्यायालय ने पुनःस्थापन देने से इंकार करते हुए प्रत्येक मजदूर को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही कोलियरी और एक ही कंपनी के दो सेट के मजदूरों को असमान व्यवहार प्राप्त हुआ है, उस मामले में मजदूरों को सामान्य मजदूरों के रूप में और वर्तमान मामले में श्रेणी IV में टिंडल की कुशल श्रेणी के रूप में कार्यरत थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि प्रथम उत्तरदाता, संदर्भ में शामिल अट्ठासी मजदूरों के सभी दावों और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान करते हुए प्रत्येक मजदूर के लिए चार लाख रुपये की राशि केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण (नंबर 2) के समक्ष जमा करे। [पैरा 7, 8] [226-सी-जी]

वर्कमेन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड **सीए 13953, 2015 दिनांक 3 अक्टूबर 2016 पर निर्भर।**

नागरिक अपीलीय अधिकारिता: नागरिक अपील सं. 11003, 2016.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 31.07.2013 के निर्णय और आदेश से, सिविल समीक्षा संख्या 118, 2010 में।

आर. डैश, वरिष्ठ अधिवक्ता, कौतभ शुक्ला, विनोध कन्ना बी., अधिवक्ताओं के साथ अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री माधुमिता भट्टाचार्य, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** द्वारा दिया गया। 1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान मामले में विवाद उन अट्ठासी मजदूरों से संबंधित है जिन्होंने केन्दुआडीह कोलियरी (प्रथम उत्तरदाता) में 'टिंडल' के रूप में काम किया था। 14 मई 1993 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(d) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विवाद का संदर्भ दिया गया:

> "क्या श्री अर्जुन पासवान और 87 अन्य व्यक्तियों की रोजगार की मांग कोलियरी मजदूर संघ द्वारा उचित है? यदि हां, तो मजदूरों को क्या राहत दी जानी चाहिए।"

टिंडल्स के कार्य विवरण के अनुसार इन मजदूरों को इंजीनियरिंग स्टोर्स, तेल और ग्रीस के ड्रम को स्थानांतरित करने में लगाया जाता था और वे संरचनाओं की स्थापना और विघटन, साथ ही मशीनरी की स्थापना और निकासी के लिए भी जिम्मेदार थे। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने 16 जुलाई 1996 के पुरस्कार में कहा:

> "यह सवाल से परे है कि ठेकेदार के अधीन काम करने वाले व्यक्ति वास्तविक हैं जो वर्तमान मजदूर हैं और उन्होंने ऐसा काम किया जो स्थायी और स्थायी प्रकृति का था और अन्य कोलियरियों में उसी प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों को नियमित किया गया था और इसलिए कोई संदेह नहीं है कि इन संबंधित मजदूरों के मामले में सौतेला व्यवहार किया गया था।"

न्यायाधिकरण ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे संबंधित मजदूरों का एक पैनल बनाएं और उन्हें वरिष्ठता के अनुसार टिंडल के काम में या किसी उपयुक्त श्रेणी में समाहित या नियमित करें ताकि सूची एक वर्ष के भीतर समाप्त हो जाए। पिछली मजदूरी से इनकार किया गया।

3. प्रथम उत्तरदाता ने पुरस्कार को चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की (सीडब्ल्यूजेसी 1655, 1997)। 18 मई 2004 को झारखंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि जब भी प्रबंधन नियमित मजदूरों को नियुक्त करना चाहता है, तो वह आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकताओं में छूट देते हुए पुरस्कार द्वारा शासित मजदूरों को प्राथमिकता देगा यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों। उच्च न्यायालय का यह आदेश अंतिम हो गया।

4. 2007 में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की (डब्ल्यूपी(एल) 4915, 2007) जिसमें 18 मई 2004 के आदेश के कार्यान्वयन की मांग की गई। 24 सितंबर 2010 को रिट याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रबंधन के इस बयान को दर्ज किया कि 18 मई 2004 को दिए गए निर्णय के बाद से टिंडल के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रबंधन का यह आश्वासन दर्ज किया कि यदि भविष्य में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और मजदूर आवेदन करते हैं, तो उन्हें पद के लिए विचार किया जाएगा और यदि किसी अन्य श्रेणी में कोई रिक्ति होती है, तो प्रबंधन भी उन्हें समायोजित करेगा।

इसके बाद, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई। एकल न्यायाधीश ने पाया कि 2004 और 2008 के बीच प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई रोजगार (11 सितंबर 2008 को आरटीआई पूछताछ के उत्तर में खुलासा किया गया) से पता चलता है कि नियुक्ति केवल अनुकंपा के आधार पर की गई थी। एक बार फिर, समीक्षा याचिका का निपटारा करते हुए प्रबंधन के इस बयान को दर्ज किया गया कि यदि और जब पदों का विज्ञापन किया जाएगा, तो मजदूर आवेदन करने के पात्र होंगे और उन्हें विचार किया जाएगा। समीक्षा याचिका की अस्वीकृति ने इन कार्यवाहियों को दायर करने के लिए प्रेरित किया।

5. अपीलकर्ता ने औद्योगिक न्यायाधिकरण में 1994 के संदर्भ 204 में हुई कुछ कार्यवाहियों पर भरोसा किया है। यह संदर्भ प्रथम उत्तरदाता की एक कोलियरी में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के अनुरोध पर था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 14 अगस्त 2000 को एक पुरस्कार पारित किया जिसमें सामान्य मजदूर श्रेणी नंबर 1 में सत्तर मजदूरों के नियमितीकरण का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 26 जुलाई 2001 को प्रबंधन की रिट याचिका को खारिज करते हुए पुरस्कार की पुष्टि की। हालांकि, पत्र पेटेंट अपील में पुरस्कार को संशोधित किया गया, जिसमें प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि जब भी वे नियमित मजदूरों को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं, तो वे आवश्यक होने पर आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को शिथिल करके संबंधित मजदूरों को प्राथमिकता देंगे। संघ ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने 18 नवंबर 2009 के निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय को रद्द कर दिया और बिना पिछली मजदूरी के पुनःस्थापन देने वाले न्यायाधिकरण के पुरस्कार को बहाल कर दिया।

6. इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलकर्ता की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उस मामले में संघ ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय को इस न्यायालय में चुनौती दी थी। वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संशोधित करते हुए 18 मई 2004 के उच्च न्यायालय के निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। वास्तव में, 2007 की अपनी रिट याचिका में मजदूरों ने 18 मई 2004 को दिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की मांग की थी। मजदूरों का दावा इसलिए उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न होना चाहिए जिसके द्वारा मजदूरों को प्रबंधन द्वारा भविष्य में रोजगार में प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया था, जिसमें आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तों में छूट दी गई थी। इस अंतर को वास्तव में इस न्यायालय द्वारा हाल ही में 3 अक्टूबर 2016 को दिए गए निर्णय में नोट किया गया है, वर्कमेन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सीए 13953, 2015)। इस न्यायालय ने पुनःस्थापन देने से इनकार करते हुए उन चौदह मजदूरों को मुआवजा दिया, जिनकी सेवाएं मुद्दे में थीं, प्रत्येक को दो लाख रुपये की राशि पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में सभी मुआवजा दावों के लिए। इस न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2016 को दिए गए निर्णय का संबंधित हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है:

> "7 मजदूरों की मूल शिकायत यह है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके परिणामस्वरूप वर्तमान कार्यवाही द्वारा शासित मजदूर, जिनमें से केवल 14 ही शेष हैं, व्यावहारिक रूप से किसी भी राहत या उपाय के बिना हैं। मजदूरों को 1987 और 1989 के बीच नियोजित किया गया था। तब से लगभग 27 साल बीत चुके हैं।

इनमें से कई 14 मजदूर सेवानिवृत्ति की आयु के कगार पर होंगे। वर्तमान में उन्हें पुनःस्थापन देने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के निर्णय में इस तरह की राहत से इनकार किया गया था जिसे चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, मजदूरों की दुविधा वास्तविक है। एक ही कोलियरी और एक ही कंपनी के दो सेट मजदूरों को असमान व्यवहार प्राप्त हुआ है। वर्तमान समूह के मजदूरों ने संख्या में ह्रास का सामना किया है और उन्हें कोई व्यावहारिक राहत नहीं मिली है। इस स्थिति का समाधान किया जाना चाहिए, जितना कि कानून में अब संभव हो, उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। पूर्ण, अंतिम और संपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, हमारा विचार है कि सभी दावों, बकाया और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान करने के लिए मुआवजा देने का आदेश न्याय की मंशा को पूरा करेगा।

8 हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि उत्तरदाता केंद्रीय सरकार के न्यायाधिकरण (नंबर 2) धनबाद के पास प्रत्येक 14 मजदूरों के लिए दो लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में जमा करेंगे। यह राशि सभी दावों, मांगों और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान होगी। राशि जमा करने के बाद, औद्योगिक न्यायाधिकरण का 9 सितंबर 1996 का पुरस्कार, जैसा कि 18 मई 2004 को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया था, को संतुष्ट के रूप में चिह्नित किया जाएगा। उत्तरदाता उपरोक्त निर्देश के अनुसार दो महीने के भीतर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण (नंबर 2) धनबाद के समक्ष संदर्भ 26, 1993 में राशि जमा करेंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पहचान की उचित पुष्टि के अधीन मजदूरों को राशि वितरित की जाएगी।"

7. वर्तमान मामले में, पहले उत्तरदाता द्वारा इस न्यायालय में दायर काउंटर एफिडेविट में यह विशिष्ट स्वीकार्यता है कि अट्ठासी मजदूर जो संदर्भ द्वारा शासित हैं, वे केन्दुआडीह कोलियरी में ठेकेदारों के माध्यम से सतह और भूमिगत खदानों में 'टिंडल' के रूप में काम कर रहे थे। काउंटर एफिडेविट में कहा गया है कि मजदूरों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नों के उत्तरों पर जो भरोसा किया जा रहा है, वह भ्रामक है और उन मामलों में नियुक्तियाँ श्रेणी 1 में की गई थीं जबकि 'टिंडल' श्रेणी IV में नियुक्त किए जाते हैं। हम इस चरण में यह नोट कर सकते हैं कि इन कार्यवाहियों की प्रक्रिया के दौरान 11 दिसंबर 2015 को एक आदेश पारित किया गया था ताकि उत्तरदाता उपरोक्त श्रेणी में रिक्तियों की स्थिति का पता लगा सकें। पहले उत्तरदाता द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 2 जनवरी 2016 को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि केन्दुआडीह कोलियरी या पूटकी बलिहारी क्षेत्र में श्रेणी IV में टिंडल के पद में कोई रिक्ति नहीं है। केन्दुआडीह कोलियरी को एक बंद खदान के रूप में बताया गया है। एक बयान संलग्न किया गया है जो अधिशेष मानव शक्ति की उपस्थिति को दर्शाता है।

8. इस न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2016 को दिए गए निर्णय में, जैसा कि पहले नोट किया गया है, पुनःस्थापन देने के लिए कारण बताए गए हैं, विशेष रूप से क्योंकि ऐसा राहत उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के निर्णय में अस्वीकृत की गई थी, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। उस मामले में मजदूर 1987-1989 के बीच नियोजित किए गए थे। लगभग सत्ताईस साल बीत चुके थे और कई मजदूर सेवानिवृत्ति की कगार पर थे। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही कोलियरी और एक ही कंपनी के दो सेट मजदूरों को असमान व्यवहार प्राप्त हुआ है, इस न्यायालय ने प्रत्येक मजदूर को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। उस मामले में मजदूर सामान्य

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, धनबाद बनाम नियोक्ता 221 एम/एस बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी

मजदूरों के रूप में नियोजित थे। वर्तमान मामले में मजदूर कुशल श्रेणी के टिंडल्स के हैं जो पहले नोट किए गए अनुसार श्रेणी ।V में आते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में यह उचित होगा कि पहले उत्तरदाता को अट्ठासी मजदूरों के सभी दावों और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान करने के लिए केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण (नंबर 2) धनबाद में प्रत्येक मजदूर के लिए चार लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए। राशि मजदूरों को उनकी पहचान की उचित पुष्टि के अधीन वितरित की जाएगी। यह राशि सभी दावों, मांगों और बकाया का पूर्ण और अंतिम निपटान होगी।

9. नागरिक अपील उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार की जाएगी। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन अपील स्वीकार की गई।

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**